

प्रेषक,

किशन नाथ,
अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन ।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 8 अगस्त, 2008

विषय :- उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तराखण्ड भवन के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यदायी संस्था, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि० इकाई 15, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष टी.ए.सी., वित्त विभाग की संस्तुति के दृष्टिगत राज्य सम्पत्ति अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-537/xxxii/2008, दिनांक 22 अप्रैल 2007 के द्वारा धनराशि रु० 464.54 लाख पर (रुपया चार करोड़ चौसठ लाख चौवन हजार मात्र) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि रु० 100.00 लाख मात्र (रुपया एक करोड़ मात्र) अवमुक्त की गई है तथा इस धनराशि को सम्मिलित करते हुए अभी तक कार्यदायी संस्था को विषयगत प्रयोजन हेतु धनराशि रु० 250.00 लाख (रुपया दो करोड़ पचास लाख मात्र) अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त के क्रम में ही चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में कार्यदायी संस्था को धनराशि रु० 100.00 लाख मात्र (रुपया एक करोड़ मात्र) पूर्ववर्ती शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- वित्त अधिकारी उत्तराखण्ड शासन उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण कर बैंक ड्राफ्ट बनाकर परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि० इकाई-15, लखनऊ को उपलब्ध करायेगा।

3- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। कार्य की अनुमन्यता निर्धारित मानकों के अनुसार है, यह भी सुनिश्चित किया जाय।

4- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उन्हीं मदों पर किया जाए, एक मद की राशि दूसरे मदों पर कदापि व्यय नहीं की जाय।

5- निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (Procurement Rules) नियमावली, 2008 में उल्लिखित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाये तथा उपर्युक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाये।

6- व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि अवमुक्त की गई धनराशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अवशेष रहती है तो, उसे उत्तराखण्ड शासन को समर्पित किया जायेगा।

(2)

7- धनराशि अवमुक्त किये जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर कार्य पूर्ण करा लिये जायेंगे।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य भवन-00-आयोजनागत-03-राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेंगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-51P/xxvii-5/2008, दिनांक 04 अगस्त, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(किशन नाथ)

अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

संख्या-502(1)/xxxii/2008 तददिनांक।

- 1- महालेखाकार,उत्तराखण्ड औबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, सुरंग एवं विद्युत गृह खण्ड-2, सिंचाई विभाग, देहरादून।
- 4- परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि० इकाई 15, लखनऊ।
- 5- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- गार्ड फाइल/एन.आई.सी.।।

आज्ञा र।

(के०एस०विष्ट)

उप सचिव।